Editorial

Fate and Future of BSNL Workers

The labourers that is workers never believe on fate, they are always having enxiety for their future. The labourer's belief on their own labour, struggle and their contribution to the nation and for that they want a better lively hood and a suitable residence, a better education for their children and a better medical facility for their family members.

The BSNL is neither a born PSU as others nor a Govt. department but it is a totally govt owned PSU. At the time of corporatization, it was committed by the govt that all the assets and liabilities will be transferred to the BSNL by its ministry of communication, keeping the assets with DOT which is essential for the public need to the govt but even after laps of 23 years of long period the assets have not been transferred rather all the liability of department of Telecom operation and Department of Telecom services were transferred to the BSNL for which the company has expended a huge amount to get rid of those liabilities such as court cases etc. Now the govt has started to take over the land parcels at prime locations one by one claiming that the owner of the company is the Govt.

So, the thought of the workers that the BSNL company has a huge back ground of land Parcells and other assets of the worth of more than one Lakh Crore has become the day dream. The workers exhorted their energy and continuously struggled to save the BSNL but now a different opinion has been arised among the workers and they are more conscious for their future. Despite the continuous guarantee given verbally by the Hon. Minister for communication in the house of parliament and out side the, workers are loosing their patient and they pressurising upon the union which is the vanguard for them from last 9-10 decades. Workers are suffering in want of implementation of the 3rd wage revision, most of the absorbed employees in BSNL after their option to work in BSNL have facing wage stagnation and they are not getting a single paisa for working years together and getting the fixed pay from 10 yrs/12 years. The promotional avenues has been reduced. Even the LICEs are not conducted for any promotional cadre with sufficient vacancies in every circle. The promotion due before VRS are not being given to the workers on the plea that those vacant posts have been abolished after a new restructuring of manpower in 2021. The employees are deprived and they are running from pillar to post for their genuine grievances to be resolved, but non is ready to hear the voice of the suffering employees. Any promotional examination for non-executives is being conducted in about half of the circles only and rest are not getting chance to sit in the examination and they are pressing upon the Unions/ Associations to do something for their carrier progression. The well educated engineers who are younger generations in the company and contributing a better services are also living in anxiety for their future carrier. Time bound financial upgradation was one way to have the employees some hope to get some increased pay and allowances through this, but this promotional policy has also not fruitful now the employees as all of them have reached the maximum of the pay span and in case of this upgradation, they are falling under stagnation. The employees are standing at such a point where if they move one step forwarded they will fall in well and if they move one step backward they have to fall in deep ditch. In such pitiable, critical situation BSNL employees are continued to serve the people of the country but neither the BSNL management nor the Govt. is taking initiative to protect, the workers with a better salary, better promotional policy and better pension after retirement which is the earned right of the workers.

To discuss and decide the further course of action a meeting of the National secretariat of NFTE (BSNL) was called on line on 23-01-2024 at 7 PM. All the circle secretaries and office bearers working at head quarter participated in the meeting and after deep discussion it was decided that viewing the situation of BSNL, without disturbance of work and work days the union will organise **"a protest cum call attention week from 12.02.2024 to 17.02.2024 to draw the attention of the union govt as well BSNL management to settle the (i) issue of implementation of the 3rd wage revision w.e.f. 01.01.2017 by providing relaxation in affordability clause for BSNL (ii) framing of new promotion policy (iii) increase of sanction strength in respect of TT, JE, JTO and JAO cadres (iv) Removal of stagnation by evolving any mechanism for the purpose."**

The workers have achieve all facilities and welfare measurers only though struggle. The entire BSNL employees have to be united to achieve their genuine demand and participate in call attention week without any if and but so that we can be able to pressurize the management and govt to settle our grievances.

There is only one way for the workers to protect themselves and to ensure a glittering future for them is the total unity and trust among them.

The NFTE (BSNL) is always stand in forefront of the workers and today also the union is making all efforts to get the ice broken and settle the burning issues like wage revision.

NFTE – ZINDABAD

WORKERS UNITY - ZINDABAD

संपादकीय

बी.एस.एन.एल. कर्मियों का भाग्य एवं भविष्य

साधारणतया मेहनतकश आवाम भाग्य पर भरोसा नहीं करते अपितु अपने कठिन परिश्रम, संघर्ष एवं राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान के मद्देनजर अपने भविष्य के प्रति चिंतित रहते हैं। लगातार कठिन श्रम एवं उतरोत्तर विकास के लिए संघर्ष के बल पर यह अपने अच्छे रहन–सहन, अच्छा आवास, बच्चों की अच्छी शिक्षा, परिवार के लिए उचित चिकित्सा का प्रबन्ध के साथ अच्छा वेतनमान एवं सेवानिवृत्ति के उपरान्त अच्छे पेंशन के लिये इनकी चिंता होती है और इसकी पूर्ति नहीं होने पर यह समुदाय आक्रोशित होता है।

बी.एस.एन.एल. अन्य लोक उपक्रमों की तरह जन्म से लोक उपक्रम नहीं है। अपितु यह संचार सेवाएं विभाग एवं संचार परिचालन विभाग को परिवर्तित कर के निगम का दर्जा दिया गया है। निगम बनाते समय सरकार ने यह लिखित रूप से आश्वस्त किया था कि निगम बनने के उपरान्त उपर्युक्त दोनों विभागों के समस्त सम्पदा एवं दायित्व नवनिर्मित निगम बी.एस.एन.एल.को हस्तानांतरित कर दी जायेगी। साथ ही जो लोकहित में आवश्यक होगा वैसे सम्पदा को रोका जा सकता है, परन्तु व्यवहार में ऐसा घटित नहीं हुआ। सरकार ने सम्पदा को हस्तानांतरित तो नहीं किया, परन्तु समस्त दायित्व बी.एस.एन.एल. को हस्तानांतरित कर दिया, जिससे बी.एस.एन.एल. को अकूत धन राशि व्यय करना पड़ा। अब सरकार बी.एस.एन.एल. की सम्पदा को एक–एक कर अधिग्रहित करती जा रही है। सरकार कहती है कि समस्त कम्पनी का स्वामित्व सरकार के पास है। इसलिए सरकार कभी भी वांछित सम्पदा का अधिग्रहण कर सकती है। इस स्थिति ने आम कर्मचारियों के मन में जो भावना पल रही है कि बी.एस.एन.एल. की अकूत सम्पदा के बल पर बी.एस.एन.एल. के लिए विकास हेतु राजस्व संग्रह किया जा सकता है। परन्तु सरकार के रवैये ने कर्मचारियों के मन मस्तिष्क को झकझोर दिया है तथा कर्मचारी वर्ग यह सोचने को मजबूर हो गये हैं कि बी.एस.एन.एल. का भविष्य में जीवंतता नजर नहीं आ रही है। हालांकि पूर्व एवं वर्तमान संचार मंत्री लोकसभा के अन्दर एवं लोक सभा के बाहर जन सभाओं में इस बात की गारंटी देते हैं कि बी.एस.एन.एल. को पुनः प्रगति के रास्ते पर लाते हुये इसके पूर्व के गौरव के अनुरूप बनाया जायेगा, परन्तु सरजमीं पर मंजर कुछ और ही है। वास्तविकता यह है कि कर्मचारी विचलित हो रहे हैं और अपना धैर्य खो रहे हैं। आम कर्मचारी यूनियन के ऊपर अत्यधिक दबाव बना रहे हैं क्योंकि पिछले नौ–दस दशकों से कर्मचारियों की हित की रक्षा करते हुये उनके जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति कराते हुये एक अच्छे नागरिक के रूप में जीवनयापन परिवार एवं बच्चों की समुचित शिक्षा एवं चिकित्सा, आवास निर्माण की क्षमता प्राप्त करा चुके थे, और वे संगठन आज अथक प्रयास करने के बावजूद भी कर्मचारियों की हित रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इसके दो कारण है – एक तो आम कर्मचारियों में संघर्ष की भावना की कमी होना तथा दूसरा संगठनों की अधिकता एवं इनके विभिन्न विचारधाराओं के कारण कर्मचारियों की अटूट गोलबंदी नहीं बन पा रही है। यही कारण है कि शासकों की मनमानी चल रही है जो पूर्व काल के इतिहास को ताजा कर रही है।

दुःखद स्थिति यह कि कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण पिछले सात वर्षों से लंबित है, डी.ओ.टी. के स्थानांतरित होकर विकल्प देने के आधार पर बी.एस.एन.एल. में समाहित कर्मचारियों का पचास प्रतिशत से ज्यादा लोग वेतन अवरूद्धता का शिकार हो चुके हैं। ऐसे कर्मचारी पिछले दस–बारह वर्षों से वेतन में बिना किसी बढ़ोत्तरी साल दर साल कार्य करते हुए कुंठा ग्रसित हो चुके हैं। पदोन्नति के रास्ते प्रायः संकीर्ण हो गये हैं। समयबद्ध वित्तिय उन्नयन की व्यवस्था चरमरा गई है। हालात ऐसे हो गये हैं कि अगर किसी कर्मचारी का वित्तिय उन्नयन होने की स्थिति में उस उन्नयन

का लाभ नहीं मिलता, अपितु उन्हें वेतन अवरूद्धता का शिकार होना पड़ता है। योग्यता के आधार पर परीक्षाओं के द्वारा पदोन्नति के रास्ते भी कठिन दौर से गुजर रहे हैं। संपूर्ण राष्ट्रीय पैमाने पर आधे से अधिक परिमंडलों में किसी भी संवर्ग में समुचित रिक्तियों के साथ परीक्षाएं नहीं की जा रही है। आधे–अधुरे परिमंडलों में नगण्य रिक्तियों के साथ परीक्षाएं संचालित की जा रही है, जिससे अधिकांश कर्मचारी पूर्णतः पदोन्नति के लाभ से वंचित कर दिये गये हैं। ऐसा स्थिति उच्च पदस्थ प्रबंधन के अधिकारियों द्वारा अदूरदर्शी तरीके से मानव संसाधन का पूर्ण गठन एवं वितरण के नाम पर बी.आर.एस. के उपरान्त 31 जनवरी 2020 के पूर्व के रिक्तियों को पूर्णतः समाप्त कर देने के कारण उत्पन्न हुआ है। समस्त कर्मचारी दु:खी हैं अर्थात अपनी समस्याओं के समाधान के लिये लगातार संघर्ष के बावजूद कामयाब नहीं हो रहे हैं। वैसे कर्मचारी जो उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त बी.एस.एन.एल. बनने के बाद कंपनी में नियुक्त किये गये हैं और कंपनी के लिये उत्तम सेवा करते हैं। इन कर्मचारियों का भविष्य बिल्कुल अंधकारमय लगता है। सरकार के कठोर बर्ताव के कारण मानव संसाधन के समस्त मानक शिथिल हो चुके हैं। श्रमिक संघों के अधिकार सीमित किये जा रहे हैं। द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा समस्याओं के समाधान की प्रथा लगभग अंतिम सांस ले रही है। स्थिति ऐसी हो गई है कि एक कदम आगे जाने पर कुएं में गिरने की स्थिति बनती है और एक कदम पीछे गहरी खाई में गिरने जैसा है।

परिस्थिति विषम एवं प्रतिकूल है और इससे निजात पाने के लिए एन.एफ.टी.ई. मुख्यालय ने दिनांक 23.01.2024 को एक ऑनलाईन मीटिंग आहुत किया जिसमें सभी परिमंडलीय सचिवों ने अपनी सहभागिता दी। विस्तृत एवं गहन विचार–विमर्श के बाद बैठक इस निर्णय पर पहुँची की अभी की परिस्थिति में बी.एस.एन.एल. के उपभोक्ता को बिना कोई दिक्कत पहुँचाए एवं कार्य दिवस की क्षति किये बगैर दिनांक 12.02.2024 से 17.02.2024 तक ध्यानाकर्षण एवं प्रतिरोध सप्ताह मनाई जाये। तदनुरूप कार्यक्रम तय करते हुए प्रमुखतः तीन भागों की सूची समर्पित की जा रही है जो इस प्रकार हैः–

1. डी.पी.ई. के दिशानिर्देश में निर्देशित आर्थिक समर्थता को शिथिल करते हुए 01.01.2017 से वेतन पुनरीक्षण की जाये तथा इसे त्वरित गति से लागु किया जाये।
2. नॉन–एक्जीक्यूटिव कर्मचारियों के लिए नई पदोन्नति नीति का सृजन किया जाये।
3. टी.टी., जेई, जे.टी.ओ. एवं जे.ए.ओ. संवर्ग के लिए निर्धारित पदों को बढ़ाई जाये।
4. वेतन अवरूद्धता को समाप्त करने के लिये कुछ विशेष व्यवस्था की जाये।

ज्ञातव्य है कि इतिहास साक्षी है कि श्रमिक समुदाय ने अभी तक जो भी प्राप्त किया है वो अपने एकजूटता एवं संघर्ष के बल पर प्राप्त किया है। अभी एक अवसर फिर आया है कि सभी श्रमिक एकजूट होकर प्रबंधन एवं सरकार पर दबाव बनायें ताकि उनकी वर्तमान ज्वलंत समस्याओं का समाधान हो सके।

कर्मचारी अपनी सुरक्षा एवं प्रगति खुद के बल पर कर सकते हैं। केवल यही एक रास्ता श्रम संगठन की अचूक मंत्र है। एन.एफ.टी.ई. सदैव ही कर्मचारी हितों के संघर्ष में अगले कतार में नजर आई है और अभी भी यह कर्मचारियों के हिफाजत दस्ता के रूप में खड़े होने को तैयार है। आपके प्रचण्ड एकता एवम् धैर्य और निष्ठा के साथ संघर्ष के द्व ारा वेतन पुनरीक्षण सहित समस्त ज्वलंत समस्याओं का समाधान करा पायेगा।

एन.एफ.टी.ई. जिंदाबाद –
कर्मचारी एकता जिंदाबाद